



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262033
CG-DL-E-28032025-262033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/ चैत्र 6, 1947

No. 95]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/ CHAITRA 6, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर) – 02/2025

विषय : मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लीयर फ्लोट ग्लास" के आयातों से संबंधित पाटन रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत - के संबंध में।

1. फा. सं. 7/04/2025-डीजीटीआर .- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, मेसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस

ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, और मेसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (जिसे इसके बाद 'आवेदक' अथवा 'याचिकाकर्ता' के रूप में भी कहा गया है) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष मलेशिया (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लीयर फ्लोट ग्लास" (जिसे इसके बाद 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदकों ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है तथा उन्होंने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने का अनुरोध किया है।

क. विगत जांच की पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2019 की अपनी जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 6/15/2019- डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 की अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/15/2019- डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को दिनांक 11 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 30/2020- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क दिनांक 10 नवंबर, 2025 तक वैध है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "4 मि. मी. से 12 मि. मी. (दोनों शामिल) तक की सामान्य मोटाई का "क्लीयर फ्लोट ग्लास" है, सामान्य मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में कहा गया है)
5. फ्लोट ग्लास पिघले हुए धातु, आमतौर पर टिन के बेड पर फ्लोटिंग मोल्टन ग्लास से बनाई गई ग्लास की एक शीट है। इस तरीके से शीट को एक समान मोटाई और बहुत ही सपाट सतह मिलती है।
6. चूंकि वर्तमान आवेदन एक सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने के लिए है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में परिभाषित किए गए अनुसार ही रहता है जो इस प्रकार है :

3. फ्लोट ग्लास में ग्लास बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामान्य कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें सामान्य तौर पर रेत, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), डोलोमाइट, चूना पत्थर, साल्ट केक (सोडियम सल्फेट) आदि शामिल होते हैं। अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। कच्ची सामग्री को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिलाया जाता है, फिर उपयुक्त क्लेट (अपशिष्ट ग्लास) के साथ नियंत्रित अनुपात में एक भट्टी में डाला जाता है, जहाँ इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। सामान्य फ्लैट ग्लास भट्टियाँ 9 मीटर चौड़ी, 45 मीटर लंबी होती हैं और इनमें 1200 टन से ज़्यादा ग्लास होता है। पिघलने के बाद, ग्लास का तापमान एक समान विशिष्ट गुरुत्व सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण, प्रशीतन, दर्पण और ऑटोमोबाइल उद्योग आदि में प्रमुख उपयोग होता है। यह उत्पाद ग्लास की बेहतर गुणवत्ता है। अपनी अंतर्निहित मजबूती, उच्च ऑप्टिकल स्पष्टता, विरूपण मुक्त चिकनी सतह आदि के कारण, उत्पाद के विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में वृद्धि हुई है।

5. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय शीर्षक 70 "ग्लास और ग्लास के बने पदार्थ" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है, यद्यपि इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 जैसे विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदकों ने इस अवस्था में किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच के शुरु होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

8. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में इस प्रकार के प्रावधान है :-

"समान वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जाने वाली जांच के अधीन वस्तु के सभी पहलुओं में समरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में, कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी पहलुओं में समान नहीं है, लेकिन उसकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तु से काफी मिलती जुलती हैं;

9. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं के समान हैं। आवेदकों ने आगे यह भी दावा किया है कि पाटित किए गए आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित की गई संबद्ध वस्तु की तकनीकी विशेषताओं, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों में कोई भी अंतर नहीं है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन मेसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है। इसके अलावा वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

11. आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि उनके अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् मेसर्स सिसैकैम फ्लैट ग्लास इंडिया और मेसर्स गुजरात गार्जियन लिमिटेड। तथापि, उन्होंने न तो जांच का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। उपर्युक्त को देखते हुए और जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों में नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग शामिल हैं, और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

12. मूल जांच में संबद्ध देश मलेशिया था। वर्तमान जांच चूंकि एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है अतः संबद्ध देश वही है जो मूल जांच में था।

च. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 माह) है। क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि शामिल होगी। संभावना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि के बाद की अवधि पर भी विचार किया जा सकता है।

छ. पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आधार

i. सामान्य मूल्य

14. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए के प्रावधानों के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, उसी तरह की वस्तु के लिए तुलनीय मूल्य, जब निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो। इसका अर्थ यह है कि संबंधित देश में उत्पादकों के घरेलू बिक्री मूल्य को सामान्य मूल्य माना जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, जब घरेलू बाजार में घरेलू उत्पादकों के बिक्री मूल्य के संबंध में सूचना उपलब्ध न हो, तो देश में उत्पाद के आयात पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि यह निर्यातक देश के घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य भी दर्शाता है। तथापि, आवेदक मलेशिया में आयात के लिए विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं है क्योंकि संबंधित वस्तुओं के लिए कोई समर्पित कोड नहीं है।
15. तदनुसार, आवेदकों ने उक्त वस्तु की उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे प्रशासनिक, विक्रय और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि के साथ समायोजित किया गया है।
16. आवेदकों द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति को जांच शुरू करने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया है।

ii. निर्यात कीमत

17. मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के लेन-देन-वार आयात संबंधी डेटा के आधार पर की गई है। मलेशिया के लिए कीमत समायोजन का दावा समुद्री माल, स्वदेशी वस्तु, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, कमीशन/व्यापारी के लाभ और गैर-वापसी योग्य वैट के आधार पर किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

18. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल *न्यूनतम स्तर* से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस बात के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मलेशिया के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं का निर्यात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित की गई कीमतों पर जारी रहा है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिकूल कीमत प्रभाव अर्थात् कीमत में कटौती, कीमत में गिरावट, तथा कीमत ह्रास के कारण लाभ में कमी, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) तथा नकदी प्रवाह में कमी के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं। इसके अलावा, आवेदकों द्वारा संबद्ध देश में उत्पादकों/ निर्यातकों के

निर्यातोनमुखी होने, अधिशेष क्षमता तथा अन्य देशों द्वारा की गई पाटनरोधी जांच के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े भी *प्रथम दृष्टया* पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर पाटन होने और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना को दर्शाते हैं।

झ. सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के जारी रहने/ उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को प्रमाणित करने तथा नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए एक सूर्यास्त समीक्षा जांच आरंभ करते हैं कि क्या ऐसे शुल्कों के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

21. समीक्षा में दिनांक 20.08.2020 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/15/2019- डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।
22. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में *यथोचित परिवर्तनों सहित* लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

23. सभी पत्राचार ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in>, <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व योग्य पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों।
24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से जुड़े ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है। ऐसी सभी सूचना इस जांच आरंभ अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के संबंध में अपने अनुरोध नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in>, <ad12-dgtr@gov.in> पर भेजी जानी चाहिए, साथ ही इसकी एक प्रति <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को भी भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (*हित की प्रकृति सहित*) से अवगत कराएं और उपरोक्त समय-सीमा के भीतर अपने प्रभावली उत्तर दाखिल करें।

ड. अगोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

30. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
31. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना किसी अंकन के किए गए ऐसे कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना के रूप में माने जाएंगे तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें कि गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
34. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए उसका अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस तरह का सारांश संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

35. हितबद्ध पक्षकार अनुरोध के अगोपनीय पाठ के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता से संबंधित मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
36. गोपनीयता के दावे पर नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और समुचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना, प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर नहीं ली जाएगी।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
38. प्राधिकारी संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

६. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध के गोपनीय पाठ को परिचालित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा सूचना को उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION****New Delhi, the 27th March, 2025****Case No. AD (SSR) - 02/2025**

Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty concerning imports of “Clear Float Glass” originating in or exported from Malaysia - reg.

1. **F. No. 7/04/2025-DGTR** .—M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd., and M/s Saint Gobain India Pvt. Ltd. (*hereinafter also referred to as “Applicants”, or “Petitioners”*) filed an application before the Designated Authority (*hereinafter also referred to as the “Authority”*) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (*hereinafter also referred to as the “Act”*) and Customs Tariff (*Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury*) Rules, 1995 as amended from time to time (*hereinafter also referred to as the “Rules”*) for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Clear Float Glass” (*hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration”*), originating in or exported from Malaysia (*hereinafter also referred to as “subject country”*).
2. The applicants alleged the likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from subject country and consequent injury to the domestic industry, and have requested for review and enhancement of the anti-dumping duty imposed on the subject goods, originating in or exported from subject country.

A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATION

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject country was initiated by the Designated Authority *vide* its Initiation Notification No. 6/15/2019 DGTR dated 23rd August 2019. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of subject goods from the subject country *vide* its final findings Notification No. 6/15/2019-DGAD dated 20th August, 2020. The recommendations of the Designated Authority were implemented *vide* Notification No. 30/2020-Customs (ADD) dated 11th November, 2020 for a period of five years. The current Anti-dumping duty is valid up to 10th November, 2025.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration (PUC) in the present investigation is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4 mm to 12 mm (*both inclusive*)”, the nominal thickness being as per BIS 14900:2000 (*hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration”*)
5. Float glass is a sheet of glass made by floating molten glass on a bed of molten metal, typically tin. This method gives the sheet uniform thickness and very flat surfaces.
6. As the present application is for initiation of a sunset review investigation, the scope of the PUC remains same as defined in the original investigation which is as follows:

3. *Float glass uses common glass-making raw materials, typically consisting of sand, soda ash (sodium carbonate), dolomite, limestone, salt cake (sodium sulfate) etc. Other materials may be used as colourants, refining agents or to adjust the physical and chemical properties of the glass. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together with suitable cullet (waste glass), in a controlled ratio, into a furnace where it is heated to approximately 1500°C. Common flat glass furnaces are 9 m wide, 45 m long, and contain more than 1200 tons of glass. Once molten, the temperature of the glass is stabilized to approximately 1200°C to ensure a homogeneous specific gravity.*
4. *The PUC finds major uses in construction, refrigeration, mirror and automobile industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes*
5. *The PUC is classified under Chapter Heading 70 "Glass and glassware" and the classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 of the Customs Tariff Act, 1975. The Customs classification is indicative only and in no way binding upon the scope of investigation.*

7. The applicants have not proposed any PCN at this stage. The parties to the present investigation may provide their comments, on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

C. LIKE ARTICLE

8. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. The applicants have submitted that subject goods which, are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. The applicants have further claimed that there are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. In addition, applicants also claimed that the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti-Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

10. The application has been filed by M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd., and M/s Saint Gobain India Pvt. Ltd. The applicants have certified that they have not imported the product under consideration from the subject country. Further, they are not related to any importer of the subject goods in India.
11. The applicants have also submitted that apart from them, there are two other producers of the subject goods in India, namely M/s Sisecam Flat Glass India and M/s Gujarat Guardian Ltd. However, they have neither supported nor opposed the investigation. In view of the above and after examination, the Authority notes that the applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules *supra*.

E. SUBJECT COUNTRY

12. The subject country in the original investigation was Malaysia. The present investigation being a sunset review investigation, the subject country is same as the original investigation.

F. PERIOD OF INVESTIGATION

13. The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st October 2023 to 30th September 2024 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI. However, the period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

G. BASIS OF LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING**i. Normal Value**

14. Under the provisions of Section 9A of the Customs Tariff Act, the normal value in relation to an article means the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory. This implies that the domestic selling price of the producers in the subject country may be considered as the normal value. Alternatively, when information regarding selling price of the domestic producers in the domestic market is not available, imports of the product into the country may be considered, as the same also represents selling price in the domestic market of the exporting country. However, applicants are not able to obtain the reliable information for imports into Malaysia, as there is no dedicated code for the subject goods.
15. Accordingly, the applicants have determined the normal value on the cost of production of the said article duly adjusted along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits.
16. The normal value methodology proposed by the applicants have been considered appropriate for the purpose of initiation.

ii. Export Price

17. The export price for subject goods from Malaysia has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) transaction wise import data. Price adjustments for Malaysia has been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, bank charges, commission/trader's profit and non-refundable VAT.

iii. Dumping Margin

18. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin determined is not only above *de-minimis* level but also significant. There is *prima facie* evidence that normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from Malaysia have continued to be exported at dumped prices, in spite of anti-dumping duty in force.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CASUAL LINK

19. The Authority notes that there is *prima facie* evidence of continuation of injury to the domestic industry on account of adverse price effect i.e., price undercutting, price depression, and price suppression leading to reduced profits, return on capital employed (ROCE) and cash flows. Further, the data provided by the applicants on the export orientation of producers/exporters in the subject country, surplus capacities and anti-dumping investigations carried out by other countries also *prima facie* indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the anti-dumping duty.

I. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of product under consideration originating in or exported from the subject country and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (IB) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

21. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. 6/15/2019-DGAD dated 20.08.2020 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject country.
22. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All communication should be sent to the Designated Authority *via* email at the email address <dir13-dgtr@gov.in>, <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in>. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
24. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority *via* email at the email addresses <dir13-dgtr@gov.in>, <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in>. within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (*including the nature of interest*) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

30. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.
31. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (*where indexation is not possible*) and such information must be appropriately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

O. NON-COOPERATION

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority